राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/109 दिनांक : 26/02/2019

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 28.02.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 – 164

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100–100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)

VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम : परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता : 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली।
अतारांकित प्रश्न संख्या : 164
प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता
दिनांक : 28.02.2019

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार सराय कालेखां पर रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) मेगा स्टेशन को रोक रही है;	जी नहीं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली–गाजियाबाद –मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर निर्माण हेतु एनसीआरटीसी की संशोधित योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा दे दी है। इस संशोधित योजना के अनुसार सराय काले खां पर एलिवेटेड स्तर पर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। डीटीआईडीसी ने सूचित किया है कि भूमिगत स्टेशन बनाए जाने की स्थिति में भी एक से अधिक एजेंसियां कार्य कर सकती है एवं बस अड्डा निर्माण कार्य समानांतर रूप से हो सकता है। स्टेशन को भूमिगत करने से कुछ देरी की संभावना अवश्य है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार की मंशा के अनुसार यदि यह स्टेशन भूमिगत बनाया जाता है तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा व प्रस्तावित होटल बनाने में कई वर्षों की देरी होगी क्योंकि ऐलिवेटेड स्तर पर स्टेशन बनाने के प्रस्ताव से एक साथ एक से अधिक एजेंसियां कार्य कर सकती है जबकि स्टेशन को भूमिगत बनाए जाने से एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है;	
ग	क्या यह भी सत्य है कि कालेखां आरआरटीएस मेगा स्टेशन को भूमिगत की बजाए ऐलिवेटेड बनाने से होने वाले खर्च में चार हजार करोड़ रूपए की बचत होगी; और	NCRTC ने सूचित किया है कि दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–अलवर और दिल्ली–पानीपत तीनों कॉरिडोर के लिए सराय काले खां में एलिवेटेड स्टेशन की योजना से इन परियोजनाओं की लागत पहले प्रस्तावित भूमिगत स्टेशन की तुलना में 4000 करोड़ रूपये घट जायेगी। हांलाकि, लागत में कमी होने की पुष्टि होना अभी शेष है, क्योंकि इन तीन कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर

K.K. DAHIYA
Special Commissioner (Tpt.)

		दिल्ली–पानीपत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अथवा इस कथन का विश्लेषण करने वाली कोई तुलनातमक रिपोर्ट अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।
घ	क्या यह भी सत्य है कि सरकार के इस निर्णय से जनसंख्या के बोझ को कम करने, वायु प्रदूषण को कम करने, सड़को पर वाहनों की भीड़ को कम कर दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने तथा दिल्ली की आधारभूत संरचनाओं की कमी को पूरा करने, अन्य राज्यों से दिल्ली में जनसंख्या के दवाब को कम करने के काम प्रभावित होंगे?	प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा दे दी है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

के. के. दहिया
विशेष आयुक्त (परिवहन)
K.K. DAHIYA
Special Commissioner (Tpt.)